पश्चिमी देशों के लिए चिंता का नया कारण

इसका कितना असर अफगानिस्तान के आम लोगों पर होता है और खुद तालिबान अपने वादों पर कितना अमल करता है, यह कुछ समय बाद स्पष्ट होगा। लेकिन इस बीच इतना तय हो चुका है कि चाहे जिस तरह की भी सरकार बने, तालिबान ही मुख्य भूमिका में होगा।

अनुज शर्मा।।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के काबिज हो जाने के बाद अब क्षेत्रीय स्तर पर उभरता नया शक्ति संतुलन न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए चिंता का नया कारण बन सकता है। हालांकि फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान काबुल एयरपोर्ट से आ रही हृदयविदारक तस्वीरों पर लगा है। तालिबान के खौफ के मारे किसी भी उपाय से जान बचाकर अफगानिस्तान से निकलने की बेकरारी में विमान के पहियों से लटके लोगों की मौत के दृश्य कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे।

अगर तालिबान को शासन करना है तो उसे आतंक और दहशत का यह माहौल बदलना होगा। अभी उसकी कोशिश दुनिया को यह एहसास दिलाने की भी है कि वह बदल गया है। यानी 1996–2001 के बीच उसने अफगानिस्तान में जो जुल्म–ज्यादतियां की थीं, इस बार नहीं होंगी। इसके जरिये वह वैश्विक समुदाय में स्वीकार्यता बढ़ाना चाहता है। इसीलिए तालिबान ने देश के अंदर आम माफी का ऐलान किया है। उसने लोगों से रूटीन लाइफ की ओर लौटने की अपील की है।

इसका कितना असर अफगानिस्तान के आम लोगों पर होता है और खुद तालिबान अपने वादों पर कितना अमल करता है, यह कुछ समय बाद स्पष्ट होगा। लेकिन इस बीच इतना तय हो चुका है कि चाहे जिस तरह की भी सरकार बने, तालिबान ही मुख्य भूमिका में होगा। इसीलिए आस–पड़ोस के कई देशों ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ सहयोग की इच्छा दर्शानी शुरू कर दी है। इनमें सबसे आगे है चीन। उसने साफ–साफ कहा है कि वह अपना भविष्य खुद गढ़ने के अफगानी लोगों के अधिकार का सम्मान करता है और उनके साथ दोस्ती और सहयोग के संबंधों का विकास जारी रखना चाहता है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद यहां तक कह दिया कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं। तालिबान से पाकिस्तान के करीबी संबंधों पर तो खैर पहले भी कोई शक नहीं था। लेकिन इस बीच रूस ने भी तालिबान के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करने की बात सार्वजनिक रूप से मानी, जो संकेत है कि दोनों पक्षों में सहयोग की जमीन तैयार हो रही है। ध्यान रहे, पिछली बार तालिबान के शासन को न तो रूस ने मान्यता दी थी और न चीन ने। तब उसे महज तीन देशों– पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई– से मान्यता मिली थी। जाहिर है, इस बार तालिबान की प्राथमिकताएं भी बदली हुई हैं। उसके प्रयासों का ही फल है कि ईरान ने अभी खुलकर कुछ भले न कहा हो, इतना संकेत उसने भी दिया है कि अगर उसके हितों पर कोई चोट न पहुंचे और सीमावर्ती शिया आबादी को न छेड़ा जाए तो सहयोग के संबंधों पर विचार करने में उसे खास दिक्कत नहीं होगी। साफ है कि चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और अफगानिस्तान का यह संभावित गठजोड़ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती साबित हो सकता है जो चीन को अपने साझा विरोधी के रूप में देखते हैं।

मेरी भूख

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

जीवन ने साधू जी से कहा की आप मुझे कोई काम दे दीजिये जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके साधू जी ने पूछा की क्या कर सकते हो तुम जीवन ने कहा की ऐसा काम जो सिर्फ बैठ कर हो सके ठमबंनेम चलना मेरे बस्का नहीं है तब साधू जी ने कहा की ठीक है तुम सब चेले के लिए तुम खाना बना सकते है। जीवन ने कहा ठीक है साधू जी ने कहा की भंडारे से कुछ समान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके खाना बना लो जीवन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए समान को लेकर चला गया साधू जी के पास सिर्फ आठ चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था उसी के हिसाब से एक चेले ने समान दे दिया और समान को लेकर जीवन चला गया और जब खाना बनाने लगा तो जीवन के सामने श्री राम जी आ गए।

संपादकीय

बैंकिंग लेन–देन पर टैक्स!

यदि सरकार 100 रुपये को डॉलर की तरह सबसे बड़ा नोट बनाए, बैंकिंग को बढ़ावा दे और बैंक के लेन–देन पर नाम मात्र का टैक्स लगाए तो उसके पास आयकर से भी बड़ा पैसा जमा हो सकता है। इसके अलावा आयकर से ज्यादा वह जायकर (खर्च पर टैक्स) पर जोर दे तो सरकारी खजाना भर जाएगा। मालदार और मध्यमवर्गीय लोग फिजूलखर्ची कम करेंगे और उससे भारी बचत होगी। बचत का यह पैसा उद्योग–धंधों में लगेगा और करोड़ों नए रोजगार पैदा होंगे। आयकर नहीं भरने या बचाने की इच्छा ही काले धन की जननी है। इस काले धन को खत्म करने के लिए ही मोदी सरकार ने नोटबंदी का जबर्दस्त कदम उठाया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। नोटबंदी का विचार जिन लोगों ने चलाया था, उनकी सारी शर्तें सरकार लागू कर देती तो शायद कालेधन पर लगाम लग सकती थी। लेकिन अब काला धन रखना ज्यादा आसान हो गया है। एक हजार का नोट खत्म किया, लेकिन सरकार ने उसकी जगह दो हजार का नोट चला दिया। नोट बदलवाने की लाइनों में खड़े सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया। नए नोट छापने में हजारों करोड़ रुपये नए सिरे से खर्च हो गए। लोग अपने धन को छिपाने से बाज आएंगे। जब धन काला नहीं होगा तो उसे वे छिपाएंगे क्यों? विदेशी बैंकों में पैसा छिपाने की कोशिश अपने आप अनावश्यक हो जाएगी और भारत का भद्रलोक उपभोक्तावाद की चक्की में पिसने से भी बचेगा।

विदेश में दुनिया के अमीरों ने जो मिल्कियत छुपा रखी है, उसकी जानकारी एक खोजी पत्रकार संगठन लेकर आया है। जिन दस्तावेजों की जानकारी इस संगठन ने सार्वजनिक की है, उसे ही 'पैंडोरा पेपर्स' कहा जा रहा है।

बड़ा भंडाफोड़ 'पैंडोरा पेपर्स'

वेद प्रताप वैदिक।।

अब से 5–6 साल पहले 'पनामा पेपर्स' ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था, अब उससे भी बड़ा भंडाफोड़ हुआ है– 'पैंडोरा पेपर्स'। 'पनामा पेपर्स' से तो पनामा नामक देश की वजह से जाने गए, लेकिन 'पैंडोरा पेपर्स' तो पैंडोरा नामक मिथकीय यूनानी महिला पैंडोरा के नाम से जाने जा रहे हैं। यूनानी देवता प्रोमिथियस ने पैंडोरा नामक परम सुंदरी को एक ऐसा बक्सा भेंट किया था, जिसमें दुनिया की सारी बुराइयां छिपा रखी थीं। विदेश में दुनिया के अमीरों ने जो मिल्कियत छुपा रखी है, उसकी जानकारी एक खोजी पत्रकार संगठन लेकर आया है। जिन दस्तावेजों की जानकारी इस संगठन ने सार्वजनिक की है, उसे ही 'पैंडोरा पेपर्स' कहा जा रहा है।

इस खोजी पत्रकार संगठन ने 14 कंपनियों के लगभग सवा करोड़ दस्तावेजों की जांच करके 2900 बैंक–खातों को पकड़ा है। इन खातों में गरीब और अमीर देशों के सैकड़ों लोगों ने 130 बिलियन डॉलर जमा कर रखे हैं। जमा करने वाले ये लोग कौन हैं? इनमें कई देशों के बादशाह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता और उद्योगपति तो हैं ही, उनके साथ कई आतंकवादी, तस्कर, फौजी, सरकारी अधिकारी, फिल्मी और खिलाड़ी लोग भी शामिल हैं। अगर भारत के 380 खाते

पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान के 700 से भी ज्यादा खाते विदेशी बैंकों में पकड़े गए हैं।

ये खाते अपने–अपने देशों में नहीं हैं। विदेशों में हैं। कुछ अपने नाम से हैं। कुछ फर्जी नाम से हैं और कुछ न्यासों (ट्रस्टों) और कंपनियों के नामों से हैं। अधिकतर खाते ऐसे छोटे–मोटे देशों में हैं, जिनके नाम भी आपने कभी नहीं सुने होंगे। जैसे बहामा, सेंट किट्स, सेंट बार्थालेमी, वनातूआ, वर्जिन आइलैंड, नौरू, बरमूडा आदि। इन देशों में लोग अपना धन इसलिए छिपाते हैं कि एक तो उन्हें वहां आयकर नहीं देना पड़ता और दूसरा कारण यह है कि उनकी गोपनीयता बनी रहती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि किसका पैसा कहां छिपा हुआ है।

उद्योगपति और व्यापारी तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा इन देशों में छिपाते हैं लेकिन नेता, अफसर, तस्कर, आतंकवादी और अपराधी अपना अनैतिक और अवैधानिक तरीकों से अर्जित धन वहां छिपाते हैं। इसीलिए जब कुछ भारतीय अखबारों में कुछ उद्योगपतियों और खिलाड़ियों के नाम उजागर हुए, तो उन्होंने सफाई पेश करनी शुरू कर दी। जो उद्योगपति खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं, उनके भी वहां करोड़ों–अरबों रुपये पाए गए हैं।

बीजेपी सरकार ने इस तरह के खाताधारियों के विरुद्ध 2015 में कड़े कानून बनाए थे। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक न तो पनामा पेपर्स के दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न अभी तक 'पेंडोरा पेपर्स' के नामों को उजागर किया गया है। जो कुछ नाम एक भारतीय अंग्रेजी अखबार ने उजागर किए हैं, उनमें भी न नेताओं के नाम हैं, न आतंकवादियों के और न ही अफसरों के। जिसका भी खाता इन विदेशी बैंकों में हो, उसका नाम बताने में संकोच की जरूरत क्या है? सांच को आंच कैसी? जरा मालूम तो पड़े कि भारतीयों के 20 हजार करोड़ डॉलर वहां जमा हैं तो किसके कितने हैं? जरा गौर करें कि पाकिस्तान के दर्जनों नेताओं, मंत्रियों, फौजियों, अफसरों और दलालों के नाम उजागर हो चुके हैं, लेकिन भारतीयों के नाम पता नहीं चल रहे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि अगर नेताओं और अफसरों के नाम उजागर हो गए तो शायद किसी भी पार्टी की कमीज सफेद न पाई जाए।

सूडोकू बवाल- 5346

*****

7							4	
		5		3			7	
					8			2
					1	9		
	2						8	
		6	7					
1			4					
	9			2		5		
	8							1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकू बवाल -5345 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

अपना ब्लॉग

राजनीति लंबे-चौड़े लेन-देन के बिना नहीं चल सकती

मोहन। बोफोर्स के लेन–देन में चाहे असली लोग बच गए, लेकिन लोगों को पता चल गया कि राजनीति लंबे–चौड़े लेन–देन के बिना चल ही नहीं सकती। पैंडोरा पेपर्स कांड में सामने आए पाकिस्तानी नामों से यह तर्क अपने आप सिद्ध हो जाता है। विदेशी बैंकों में यह पैसा नेता और अफसर लोग इसलिए छिपाते हैं कि इसका पता किसी को भी नहीं चले। यदि यह पैसा उसी तरह भारत में भी छिपाकर रख सकते हों तो शायद टैक्स भरने में भी उन्हें कोई एतराज न हो, क्योंकि उनके सैकड़ों विश्वसनीय अनुयायियों के नाम से वे खाते खोलकर टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन वे अपने साथियों को भी इस गुप्त धनराशि का सुराग नहीं लगने देना चाहते। लेकिन व्यापारियों और उद्योपतियों को यदि आयकर भरने का डर न हो तो उन्हें अपनी कमाई छिपाने का कोई कारण नहीं है। दुनिया के 23 देश ऐसे हैं, जिनमें आयकर नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अधिकतर वे सभी छोटे–छोटे देश हैं। उनके सरकारी खर्च भी कम हैं, मगर भारत–जैसे बड़ी जनसंख्या वाले और विशाल देश की सरकार यथेष्ट आमदनी के बिना कैसे चल सकती है?